



BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस: ऊर्जा की बचत, सुरक्षित भविष्य

दिसंबर 14, 2025

प्रमुख उपलब्धियां

- पीएम सूर्य घर मिशन के तहत दिसंबर 2025 तक 7 गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा जोड़ी गई है और लगभग 24 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है।
- परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) में बदलाव एक बड़ा कदम है, जिससे उद्योगों की ऊर्जा नीति में कार्बन उत्सर्जन कम करने और कार्बन क्रेडिट के व्यापार को केंद्र में रखा गया है।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म ऊर्जा दक्षता की व्यवस्था को आधुनिक बना रहे हैं, जिससे निगरानी, नियमों का पालन और पारदर्शिता बेहतर हो रही है।
- भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता अब 50 प्रतिशत से अधिक गैर-जीवाश्म ऊर्जा तक पहुंच चुकी है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, ऊर्जा दक्षता योजनाओं और ग्रिड की मजबूती को दर्शाती है।

परिचय

ऊर्जा केवल बिजली या ईंधन ही नहीं है; यह वह शक्ति है जो आधुनिक जीवन को संभव बनाती है। यह हमारे घरों को रोशन करती है, उद्योगों को चलाती है, परिवहन को गति देती है, डिजिटल सेवाओं को सहारा देती है और अस्पतालों, स्कूलों व व्यवसायों को लगातार चालू रखती है।

ऊर्जा आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और तकनीकी उन्नति की बुनियाद है। जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती मांग को पूरा

करने के लिए केवल ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाना ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का कुशल और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

ऊर्जा दक्षता का अर्थ है कम ऊर्जा का उपयोग करके वही काम करना, जबकि ऊर्जा संरक्षण का मतलब है ऊर्जा की बर्बादी को रोकना। ये दोनों मिलकर भारत की ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। इसी महत्व को देखते हुए, ऊर्जा के कुशल उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों को सम्मान देने के लिए भारत में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस वर्ष 1991 से हर साल मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऊर्जा की खपत कम करने और सभी क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के लागू होने के बाद, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने देशभर में इस दिशा में प्रयासों का नेतृत्व करना शुरू किया। इनमें जागरूकता कार्यक्रम, स्कूलों में प्रतियोगिताएं और राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। आज यह दिवस इस बात की याद दिलाता है कि ऊर्जा दक्षता न केवल ऊर्जा को किफायती बनाने में मदद करती है, बल्कि उत्सर्जन घटाने, बिजली ग्रिड को मजबूत करने और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने में भी अहम भूमिका निभाती है।

Objectives of National Energy Conservation Day



Raising Awareness

Spread understanding of why saving energy matters in daily life.

Promoting Energy Efficiency

Encourage the use of efficient appliances, technologies, and practices.

Reducing Energy Wastage

Motivate people to avoid unnecessary or excessive energy use.

Fostering Responsibility

Build a culture of conscious and responsible energy consumption among citizens.

Supporting Policy Goals

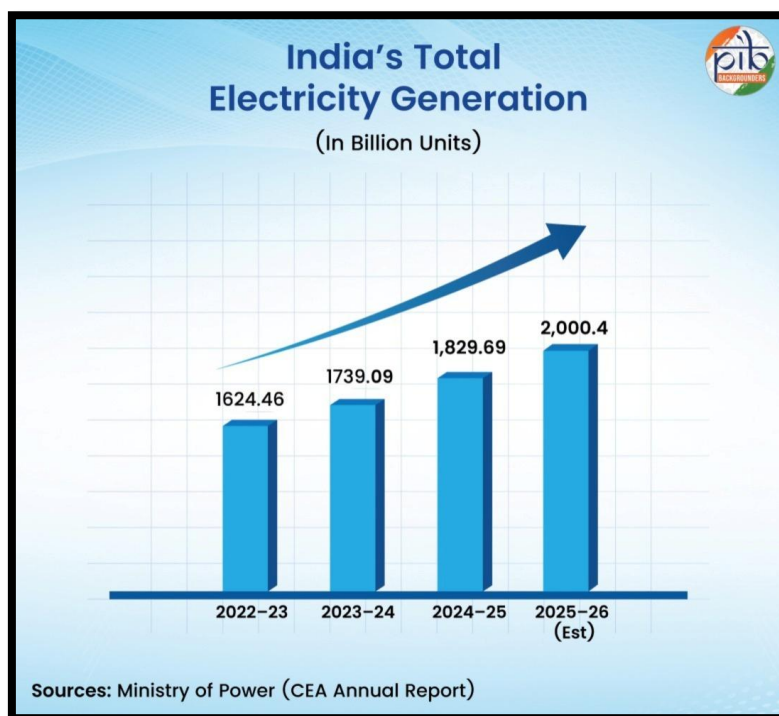
Reinforce national efforts to lower energy intensity and advance sustainability.



Source: Ministry of Power

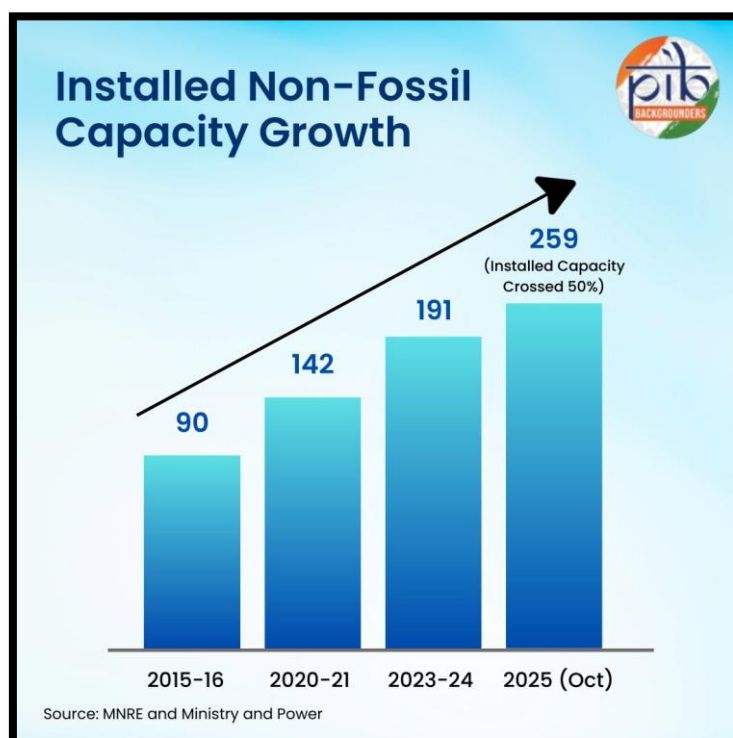
भारत का वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य

भारत दुनिया के टॉप तीन एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक है और बिजली की डिमांड हर साल बढ़ रही है। कुल बिजली जेनरेशन 2023-24 में 1,739.09 बिलियन यूनिट्स (BU) से बढ़कर 2024-25 में 1,829.69 BU हो गया, जो 5.21% की बढ़ोतरी है। 2025-26 के लिए जेनरेशन का टारगेट 2,000.4 BU रखा गया है।



साथ ही, पावर सिस्टम ज़्यादा भरोसेमंद हो गया है। जून 2025 में, एनर्जी की कमी का लेवल 0.1% जितना कम बताया गया था। भारत में ज़ीरो कमी के साथ **241 GW की पीक डिमांड** रही, जो बेहतर सिस्टम रेजिलिएंस और बेहतर डिमांड-सप्लाई मैनेजमेंट को दिखाता है।

भारत का ऊर्जा मिश्रण तेज़ी से **स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों** की ओर बढ़ रहा है। **31 अक्टूबर 2025** तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता **505 गीगावॉट** हो चुकी है, जिसमें से **259 गीगावॉट से अधिक क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों** से आती है। इसका मतलब है कि अब भारत की **50 प्रतिशत से अधिक बिजली क्षमता सौर, पवन, जल और परमाणु ऊर्जा जैसे गैर-जीवाश्म स्रोतों** से प्राप्त हो रही है। यह बदलता परिदृश्य दर्शाता है कि भारत न केवल ऊर्जा की पहुंच बढ़ा रहा है, बल्कि एक **स्वच्छ, हरित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य** की दिशा में भी लगातार आगे बढ़ रहा है।



प्रमुख ऊर्जा संरक्षण पहल

ऊर्जा की बर्बादी कम करने और संसाधनों का सही इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने इंडस्ट्रीज़ में कई नेशनल प्रोग्राम शुरू किए हैं, जो अच्छी टेक्नोलॉजी, बेहतर डिज़ाइन और स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट को बढ़ावा देते हैं।

तरक्की को बढ़ावा देने वाले खास सरकारी प्रोग्राम हैं:

औद्योगिक ऊर्जा दक्षता: उद्योग क्षेत्र भारत की कुल ऊर्जा खपत का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए ऊर्जा दक्षता में सुधार लागत कम करने और उत्सर्जन घटाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

- कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) भारत का नया बाजार-आधारित औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन फ्रेमवर्क है। इस स्कीम के तहत, उत्सर्जन-गहन क्षेत्रों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य दिए जाते हैं। जो उद्योग इन लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलते हैं, जिन्हें बाजार में व्यापार किया जा सकता है।

दिसंबर 2025 में सरकार ने कई प्रमुख ऊर्जा-गहन उद्योगों जैसे एल्युमिनियम, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी, पल्प और पेपर, टेक्सटाइल्स और क्लोर-एल्कली को पुराने PAT (Perform, Achieve and Trade) तंत्र से CCTS अनुपालन तंत्र में स्थानांतरित कर दिया।

परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना भारत की औद्योगिक ऊर्जा दक्षता के लिए एक बुनियादी कार्यक्रम थी। PAT योजना में नामित उपभोक्ताओं को ऊर्जा-कम करने के लक्ष्य दिए जाते थे, और जो उद्योग इन लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करते थे, उन्हें एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट (ESCerts) मिलते थे, जिन्हें बाजार में ट्रेड किया जा सकता था। PAT ने बड़े पैमाने पर ऊर्जा दक्षता सुधारों की नींव रखी, जिसे अब CCTS आगे बढ़ा रहा है, जो प्रदर्शन को सीधे कार्बन-उत्सर्जन परिणामों से जोड़ता है।

घरेलू ऊर्जा दक्षता: भारत की ऊर्जा संरक्षण रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है घरों और छोटे व्यवसायों में ऊर्जा दक्षता में सुधार।

- **स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग (S&L) प्रोग्राम:** यह योजना 28 उपकरण श्रेणियों (जिनमें से 17 अनिवार्य) को कवर करती है और उपभोक्ताओं को स्टार लेबल के माध्यम से स्पष्ट जानकारी देती है। यह निर्माताओं को उच्च दक्षता वाली तकनीक अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। हाल ही में शामिल किए गए उपकरण, जैसे ग्रिड-संयुक्त सोलर इनवर्टर, इस कार्यक्रम के निरंतर विस्तार को दर्शाते हैं।
- **उजाला एलईडी प्रोग्राम:** जनवरी 2015 में शुरू किया गया उन्नत ज्योति द्वारा सभी के लिए किफायती एलईडी (उजाला) योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को किफायती कीमत पर ऊर्जा-कुशल एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना है। यह पहल न केवल बिजली के बिल कम करती है, बल्कि ऊर्जा की बचत भी करती है और ऊर्जा-कुशल उपकरणों के लिए एक बड़ा और प्रतिस्पर्धी बाजार बनाने में मदद करती है।

उजाला एलईडी प्रोग्राम अब पूरे देश में विस्तारित हो चुका है और इसके तहत 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। इस पहल के परिणामस्वरूप हर साल 47,883 मिलियन kWh ऊर्जा की बचत, ₹19,153 करोड़ लागत की बचत, 9,586 MW पीक मांग में कमी, और 3.88 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी हुई है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इस कार्यक्रम ने ऊर्जा दक्षता, लागत बचत और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

- **प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (2024)** फरवरी 2024 में ₹75,021 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य एक करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर सिस्टम से लैस करना और प्रत्येक माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। दिसंबर 2025 तक, 23.9 लाख से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉल किया जा चुका है।

- **RDSS:** 2021 में शुरू की गई रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (DISCOMs) के ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मजबूत करने के लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। दिसंबर 2025 तक, भारत ने सेंट्रल और DISCOM द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम के तहत 4.76 करोड़ स्मार्ट बिजली मीटर लगाए हैं।

बिल्डिंग्स: भारत ने बेहतर कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देने और नई बिल्डिंग्स में बिजली का इस्तेमाल कम करने के लिए बिल्डिंग-एनर्जी कोड बनाए हैं।

- **एनर्जी कंजरवेशन बिल्डिंग कोड (ECBC),** जिसे सबसे पहले 2007 में लागू किया गया था, वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा दक्षता मानक तय करता है। इसे बाद में वाणिज्यिक और आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता और सतत निर्माण संहिता (ECSBC) के माध्यम से और मजबूत किया गया, जो अब **सस्टेनेबिलिटी, निर्माण सामग्री और समग्र पर्यावरण प्रदर्शन** को भी कवर करता है।
- **इको निवास संहिता (ENS)** 2018 में घरों के लिए पेश की गई, जो **बेहतर डिजाइन, वेंटिलेशन और इन्सुलेशन** के जरिए आवासीय भवनों में ऊर्जा खपत कम करने पर केंद्रित है। ये दोनों कोड मिलकर **कम्फर्ट बढ़ाते हैं, ऊर्जा बिल घटाते हैं और भारत के दीर्घकालीन ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों** का समर्थन करते हैं।

डिजिटल और संस्थागत ढांचे: ऊर्जा दक्षता को सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से लागू करने के लिए **संस्थाओं और डेटा सिस्टम** को मजबूत करना आवश्यक है।

- **ऊर्जा दक्षता इन्फॉर्मेशन टूल (UDIT)** जैसे डिजिटल टूल, ऊर्जा खपत के पैटर्न, प्रोग्राम परफॉर्मेंस और सेक्टर के हिसाब से बचत के बारे में देश भर में जानकारी देते हैं।
- **नेशनल मिशन ऑन एन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी (NMEEE)** PAT, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी (MTEE), एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म (EEFP), और फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट (FEEED) जैसी पहलों के जरिए पूरी पॉलिसी का ढांचा देता है।
- **LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट)** के तहत व्यवहार से जुड़ी पहल, सोच-समझकर और ज़िम्मेदार खपत को बढ़ावा देकर लोगों की भागीदारी को और मजबूत करती हैं।

जनभागीदारी: देशभर में **पुरस्कारों और चित्रकला प्रतियोगिताओं** के माध्यम से जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA), जिसे 1991 से हर साल 14 दिसंबर को आयोजित किया जाता है, भारत के प्रमुख **ऊर्जा दक्षता सम्मान** में से एक है। यह उद्योगों, संगठनों और व्यक्तियों की उत्कृष्ट ऊर्जा-संरक्षण उपलब्धियों को मान्यता देता है। साल 2021 से, **राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता**

नवाचार पुरस्कार (NEEIA) भी आयोजित किए जा रहे हैं, जो ऊर्जा दक्षता में नवीनतम नवाचारों को उजागर करते हैं।

इसके अलावा, **राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण चित्रकला प्रतियोगिता** भी हर साल 14 दिसंबर को आयोजित की जाती है। यह देश का एक सबसे बड़ा छात्र जागरूकता अभियान है, जिसे स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों को ऊर्जा बचाने के विषयों को रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना और सतत प्रथाओं के प्रति प्रारंभिक जागरूकता विकसित करना है।

भारत का वैश्विक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां

साल 2024 में, भारत ने आधिकारिक रूप से **इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब** में शामिल होकर एक वैश्विक मंच से जुड़ाव किया, जहाँ सरकारें, अंतरराष्ट्रीय संगठन और निजी क्षेत्र के हितधारक ऊर्जा-कुशल तकनीकों और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करते हैं। यह कदम भारत की घरेलू ऊर्जा दक्षता प्रयासों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मेल कराने और अपने अनुभवों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संयुक्त राष्ट्र की **क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)** के तहत, प्रत्येक देश से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप ऊर्जा संक्रमण मार्ग तैयार करे। भारत ने ऐसा मार्ग निर्धारित किया है जो तेजी से आर्थिक विकास और दीर्घकालीन जलवायु जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाता है। भारत ने 2070 तक **नेट-जीरो उत्सर्जन** प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत 2030 के राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs) में शामिल हैं: GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना, स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से सुनिश्चित करना, 2.5-3 अरब टन CO₂ समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना, LIFE आंदोलन के माध्यम से सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना, और जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में लचीलापन बढ़ाना। इन पहलों के माध्यम से भारत **ग्लोबल साउथ** का प्रमुख प्रतिनिधि बनकर उभरा है, जो सस्ती स्वच्छ ऊर्जा, समान जलवायु वित्त और तकनीक तक पहुंच के लिए UNFCCC के सिद्धांतों के अनुरूप आवाज उठाता है। अपने G20 अध्यक्षता के दौरान, भारत ने स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा संक्रमण पर वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाया, जिसमें **ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (GBA)** की शुरुआत भी शामिल है।

अब तक, ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (GBA) में 25 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हो चुके हैं, जो सतत ईंधनों के क्षेत्र में भारत की नेतृत्व क्षमता पर वैश्विक भरोसे को दर्शाता है। यह गठबंधन प्रमुख बायोफ्यूल उत्पादकों, उपभोक्ताओं और बहुपक्षीय संस्थाओं को एक साथ लाकर किफायती और कम-कार्बन ईंधनों को दुनिया भर में तेजी से अपनाने का प्रयास करता है।

क्या आप जानते हैं?

ऊजाला का एलईडी -बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मलेशिया के मेलाका राज्य ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) के साथ एक एग्रीमेंट के तहत UJALA-टाइप स्कीम अपनाई है। इससे पहले, सरकार ने एफिशिएंट लाइटिंग को बढ़ावा देने के लिए UJALA-UK लॉन्च किया था।

भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) की भी सह-स्थापना की, जो विकासशील देशों में सस्ती सौर ऊर्जा का विस्तार करने का काम करता है। ISA वैश्विक निवेश जुटाने, सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ में सौर ऊर्जा के तेजी से विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख मंच बन गया है।

आईएसए 2025 की प्रमुख बातें

- भारत ने नई दिल्ली में 8वीं ISA असेंबली होस्ट की, जिसमें 125+ मंत्र और सिग्नेटरी देश, 550 प्रतिनिधि और 30+ मंत्री शामिल हुए, जिससे आईएसए का दुनिया भर में बढ़ता असर और मजबूत हुआ।
- आईएसए ने कई नई वैश्विक सौर पहल शुरू कीं, जिनमें शामिल हैं:
 - SUNRISE, जो सौर ऊर्जा रीसाइक्लिंग और सर्कुलैरिटी को बढ़ावा देता है;
 - OSOWOG (One Sun One World One Grid), जो सीमा-पार सौर ग्रिड इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाता है;
 - SIDS Solar Procurement Platform, जिसे विश्व बैंक के सहयोग से छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए विकसित किया गया है;
 - Global Capability Centre (GCC), जो नवाचार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मजबूत करता है।
- आईएसए ने अपनी “1000 की ओर” रणनीति को आगे बढ़ाया, जिसका लक्ष्य 2030 तक सौर निवेश में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना और सदस्य देशों में 1,000 गीगावाट सौर क्षमता की तैनाती का समर्थन करना है।

ISA के अलावा, भारत कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI), मिशन इनोवेशन, और अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) के साथ साझेदारियों जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। इन पहलों के जरिए भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को समर्थन देने और उसे आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है।

IRENA नवीन ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार, भारत की रैंक:

- सौर ऊर्जा में तीसरा
- वायु ऊर्जा में चौथा, और
- कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथा स्थान

आगे का रास्ता: NDCs, नेट जीरो और विकसित भारत में भूमिका

ऊर्जा संरक्षण आज भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) इस यात्रा में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, PAT/CCTS, बिल्डिंग एनर्जी कोड, NECA/NEEIA, ऊर्जा ऑडिट, राज्य साझेदारियां और बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान जैसी पहलों के माध्यम से BEE यह सुनिश्चित कर रहा है कि ऊर्जा दक्षता दैनिक निर्णयों का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाए। इसके जागरूकता कार्यक्रम, जैसे स्कूल चित्रकला प्रतियोगिताएं, जनसंपर्क अभियान और राष्ट्रीय पुरस्कार, युवा, घर और व्यवसायों को यह समझने में मदद करते हैं कि हर बचाई गई ऊर्जा इकाई राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देती है।

जैसे ही देश राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाता है, आगे का मार्ग स्पष्ट है: ऊर्जा संरक्षण केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि नागरिकों की जिम्मेदारी भी है। सरकार, BEE, उद्योग और नागरिकों को मिलकर एक सूचित और दक्षता-केंद्रित संस्कृति विकसित करनी होगी, जो भारत के स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के विज़न का समर्थन करे। ऊर्जा संरक्षण भारत की विकास रणनीति का अभिन्न हिस्सा बना रहेगा, जैसे-जैसे देश 2030 के जलवायु लक्ष्यों और दीर्घकालीन विजन विकसित भारत की ओर बढ़ता है।

पीआईबी रिसर्च

संदर्भ

बिजली मंत्रालय:

https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/power_sector_at_glance_Sep_2025.pdf

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2090639®=3&lang=2>

<https://powermin.gov.in/en/content/energy-efficiency>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2200456®=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2135450®=3&lang=1>

https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/MOP_Annual_Report_Eng_2024_25.pdf

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2179463®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2061656®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx/pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2089243®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1513648®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1489805®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=170569®=3&lang=2>

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो:

https://beeindia.gov.in/sites/default/files/press_releases/Brief%20Note%20on%20PAT%20Scheme.pdf

<https://udit.beeindia.gov.in/standards-labeling/>

<https://udit.beeindia.gov.in/about-udit/#:~:text=Home%20/%20About%20UDIT,Informing%20policy%20and%20NDC%20goals>

पीआईबी अभिलेखागार:

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=156347&NotelId=156347&ModuleId=3®=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149086®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149088®=3&lang=2>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1885731®=3&lang=2>

केंद्रीय मंत्रिमंडल:

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1847812®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1837898®=3&lang=2>

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2036867®=3&lang=2>

<https://mopng.gov.in/en/page/68>

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2071486®=3&lang=2>

<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3716e1b8c6cd17b771da77391355749f3/uploads/2025/11/202511061627678782.pdf>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2036867®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1606776®=3&lang=2#:~:text=Cumulative%20renewable%20energy%20capacity%20of,was%20given%20by%20Shri%20R.K>

<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3716e1b8c6cd17b771da77391355749f3/uploads/2024/10/20241029512325464.pdf>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183434®=3&lang=2>

https://sansad.in/getFile/annex/269/AU1111_Djrfhp.pdf?source=pqars

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2200441®=3&lang=2>

गृह मंत्रालय

<https://ndmindia.mha.gov.in/ndmi/leadership-initiatives>

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

<https://mi-india.in/>

अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता:

<https://www.irena.org/News/pressreleases/2022/Jan/India-and-IRENA-Strengthen-Ties-as-Country-Plans-Major-Renewables-and-Hydrogen-Push>

Ibef:

<https://www.ibef.org/industry/power-sector-india>

पीके/केसी/वीएस